(Rs. in crores

Year	Net Profit (BALCO)	Loss at Bidhanbagh Unit (West Bengal)	Derived Profit Korba Plant. M. P without taking into account the loss incurred by Bidhanbag Unit.
1990-91	1.77	—4.55	6.32
1991-92	1.38	—3.45	4.83
1992-93	2.59	—5.35	7.94

(b) The installed capacity of Korba Aluminium Complex is 1,00,000 tonnes of saleable metal per annum. The production of saleable metal for the last three years is given below:

Year	Production (in tonnes)
1990-91 . . .	91,745
1991-92 . .	92,011
1992-93 . . .	91,.47

Investment made as on 31-3-1993 is given below :—

1. Korba (including two Captive mines at Amarkantak and Phutkapahar).	— Rs. 344.90 crores.
2. Captive Power Plant	— Rs. 437.32 crores.
TOTAL :	— Rs. 782.22 crores.

(c) No Sir.

(d) and (e) Do not arise.

राज्य सरकारों को खानों का आवंटन

2194. **श्री शिव चरण सिंह :** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केंद्र सरकार नियम बनाकर राज्य सरकारों को खानों का आवंटन करती है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा नियमों/कानूनों का उल्लंघन किए जाने के मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और गत तीन वर्षों के दौरान कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या यह सच है कि खान के प्रत्येक पट्टाधारी को खान का संचालन स्वयं करना चाहिए और इसे आगे किराए पर देना कानूनी अपराध है ; यदि हां, तो क्या विभाग इसकी जांच करता है ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो कितने पट्टों को रद्द किया गया है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) खनिज राज्य सरकारों की सम्पत्ति है, जो कानून के मुताबिक खनन रियायतें मंजूर करती है । केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को कोई खान आवंटित नहीं करती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं । पट्टों को आगे किराए पर देने की शर्तें खनिज रियायत नियम के नियम 37 में दी गई है ।

Development of Malanjkhand Deposits

2195. **MISS SAROJ KHAPARDE:** Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether Government have since examined the detailed feasibility report

in respect of development of Malanjkhand Deposits which was submitted by M/s Bishimetal Corporation of Japan in June, 1992; and

(b) if so, what decision Government have taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) and (b) Government has not examined the feasibility report prepared by M/s Bishimetal Exploration Co. However, a review of the expension schemes of Hindustan Copper Ltd. indicates that setting up of a Smelter at Malanjkhand based on indigenous copper concentrates is not presently viable

Deputation of experts from Geological Survey of India to study aspects of the earthquakes

2196. SHRI GHUFRAM AZAM: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether the Geological Survey of India has decided to send four teams of experts to study various aspects of the devastating earthquake that occurred in Latur and Osmanabad districts of Maharashtra recently;

(b) if so, the details of the reports submitted by the expert teams to Government;

(c) whether Government have contemplated any further action on the basis of reports of the expert committee; and

(d) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) to (d) Yes, Sir. Geological Survey of India (GSI) has sent teams of experts comprising geologists and geo-physicists to carry out post-earthquake damage survey, for preparation of isoseismal maps and seismotectonic studies of the areas. Further suitable action will depend upon the finding of the teams.

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में व परियोजनाओं से खनिजों का नुकसा

2197. श्री राम नरेश या व : व खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उत्तर प्रदेश में कई बांध पर योजनाओं और मध्य प्रदेश में नर्मदा पर योजना के कारण खनिज पदार्थों व कितना नुकसान हुआ है और इससे कौ कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश औ मध्य प्रदेश में नुकसान का अलग-अल आकलन क्या है ; और

(ग) क्या इन परियोजनाओं के कार खनिजों के सम्भावित नुकसान के बा में कोई सर्वेक्षण कराया गया था ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्र बलराम सिंह या व) : (क) बांध पर योजनाओं से खनिजों को कोई नुकसा नहीं होता । हालांकि और बाढ़ी के जल मग्न होने के कारण खनिज निष्कर्ष के लिए अन्य तकनीकी को जरूरत प सकती है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Tripartite Agreement for sub-leasin Bartes Mines at Mangampet

2198. DR. NARREDDY THUL REDDY: Will the Minister of MIN be pleaed to state:

(a) whether Government of And Pradesh have requested to cancel Tripartite agreement and to cancel sub-lease to private persons by the And Pradesh Mining Corporation with rega to Bartes Mines at Mangampet Anantharajupet in Cuddapah district Andhra Pradesh;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what action has been taken by Central Government thereon?